



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (प्रकाशरण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 28 जनवरी, 2005/8 माघ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 2005

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-22/2004-लेज. - हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27-1-2005 को अनुमोदित

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक 15) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)।

2005 का अधिनियम संख्यांक 7.

**हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन)
अधिनियम, 2004**

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2005 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986
(1987 का 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 है। | संक्षिप्त नाम। |
| 2. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— | धारा 8-क का अन्तः-स्थापन। |

"8-क. राज्य सरकार की जांच करने की शक्ति.—राज्य सरकार, अपने किन्हीं अधिकारियों या अभिकरण द्वारा, जैसा यह निर्देश दे, विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित संस्थाओं के प्रशासन और वित्त प्रबन्धन से सम्बद्ध किन्हीं मामलों पर जांच करवा सकेगी और ऐसी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार इसका परीक्षण करने के पश्चात् रिपोर्ट को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी और कुलपति को हटाए जाने सहित किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की भी सिफारिश करेगी यदि इसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो इस अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (6) में अन्तर्निहित हैं और कुलाधिपति तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु कुलाधिपति ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेगा।"

- | | |
|---|-------------------|
| 3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (i) का लोप किया जाएगा। | धारा 9 का संशोधन। |
|---|-------------------|

- | | |
|---|---------------------------|
| 4. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— | धारा 9-क का अन्तःस्था-पन। |
|---|---------------------------|

"9-क. शिक्षा और अनुसंधान परिषद् की बैठक.—शिक्षा और अनुसंधान परिषद् की, अध्यक्ष द्वारा नियत तारीख, समय और स्थान पर वर्ष में तीन बार बैठक होगी।"

धारा 25
का
संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 25 में, उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(7) कुलपति, आपात स्थिति में जिसमें उन शक्तियों, जो उसमें निहित नहीं हैं, की वास्तव तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, कारणों को अभिलिखित करके ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और मामले को ऐसे प्राधिकरण, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम हो, के समक्ष इसकी ठीक आगामी बैठक में पुष्टि के लिए रखेगा न कि साठ दिन के पश्चात्, ऐसा न होने पर, उस द्वारा की गई कार्रवाई प्रभावहीन हो जाएगी और यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि ऐसे प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती है तो वह भी प्रभावहीन हो जाएगी :

परन्तु कुलपति द्वारा ऐसी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, किसी पोजीशन या समनुदेशन पर कोई नियुक्ति करने या किसी पदधारी को ऐसी पोजीशन या समनुदेशन से हटाए जाने के लिए नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई भी बात कुलपति को किसी भी प्रकार के ऐसे व्यय को, जो बजट में सम्यक् रूप से प्राधिकृत या उपबन्धित न हो, उपगत करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी।”।

धारा 30
का प्रति-
स्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“30. रजिस्ट्रार (कुल सचिव).—(1) विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार (कुल सचिव) होगा जो विश्वविद्यालय के सिनेट, बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(2) इस अधिनियम की धारा 26 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार उन अधिकारियों में से जिनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल हो या राज्य सरकार के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कम से कम 9 वर्ष का सेवाकाल हो, राज्य सरकार द्वारा, ऐसा न होने पर, चयन समिति, जैसी इस प्रयोजन के लिए परिनियमों के अधीन गठित की जाए, की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा, नियुक्त किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार (कुल सचिव) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।”।

धारा 31
का
संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 31 में, उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) एक लेखा नियन्त्रक होगा जिसे हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवाओं (सामान्य शाखा) के अधिकारी (अधिकारियों) में से, जो उप-लेखा नियन्त्रक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह बजट और लेखा विवरण की तैयारी और प्रस्तुति सहित विश्वविद्यालय के लेखों से सम्बन्धित समस्त मामलों के लिए विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।”।

12. मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 39-क
का
अन्तःस्थापन।

“39-क. पदों इत्यादि का सृजन.—विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किसी पद, पोजीशन और समनुदेशन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि यह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो।”।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No 7 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE,
HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) ACT, 2004

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH JANUARY, 2005)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture,
Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).*BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the
Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of
Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2004.Insertion of
section 8-A.2. After section 8 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture,
Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter referred to as the
“principal Act”), the following section shall be inserted, namely:—

“8-A. *Power of State Government to enquire.*—The State Government
may, cause an enquiry to be made by any of its officers or agency,
as it may direct on any matters connected with the
administration and finances of the University or the institutions
maintained by it and the report of such enquiry shall be sent to
the State Government and the State Government after exam-
ining the same, shall forward the report to the Chancellor and
may also recommend any action including removal of Vice-
Chancellor, if in its opinion there exist such circumstances as
are contained in sub-section (6) of section 24 of this Act and
the Chancellor may take action accordingly :

Provided that before taking such action, the Chancellor shall afford
reasonable opportunity of being heard to the Vice-Chancellor.”.Amendment
of section 9.3. In section 9 of the principal Act, in sub-section (2), the existing
clause (i) shall be omitted.Insertion of
section 9-A.4. After section 9 of the principal Act, the following section shall be
inserted, namely:—

“9-A. *Meeting of the Council for Education and Research.*—The
Council for Education and Research shall meet thrice in a
year, on the date, time and place fixed by the Chairman.”.

Amendment
of section
11.

5. In section 11 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) in clause (A), the existing sub-clause (iii) shall be
omitted; and

(b) in clause (B), the existing sub-clause (iii) shall be omitted.

6. In section 12 of the principal Act,—

Amendment
of section
12.

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (A), the existing sub-clause (iii) shall be omitted;
and

(ii) in clause (B), the existing sub-clause (iii) shall be omitted; and

(b) in sub-section (2), for the words and sign “non-member Secretary”, the words and sign “Member-Secretary” shall be substituted.

7. In section 19 of the principal Act,—

Amendment
of section
19.

(a) in sub-section (1), after sub-clause (ii), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(ii-a) Principal Secretary or Secretary (Agriculture) to the State Government ;

(ii-b) Principal Secretary or Secretary (Horticulture) to the State Government;

(ii-c) Registrar;” and

(b) in sub-section (2), for the words and sign “non-member Secretary”, the words and sign “Member-Secretary” shall be substituted.

8. In section 24 of the principal Act.—

Amendment
of section
24.

(a) after sub-section (3), the following sub-sections shall be added, namely:—

“(3-a) The Chancellor, by general or special order, may place the Vice-Chancellor under suspension,—

(a) where an enquiry under sub-section (6) of this section is contemplated or is pending ; or

(b) where in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University ; or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or

(d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (e. g. apprehended tampering with documents or to influence witnesses).

(3-b) The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows:—

- (i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, not directly attributable to the Vice-Chancellor;
- (ii) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor; and
- (iii) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clauses (i) and (ii).

(3-c) No payment under sub-section (3-b) shall be made unless the Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.”; and

(b) at the end of sub-section (6), the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 8 or section 8-A of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub-section but the Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.”.

Amendment
of section
25.

9. In section 25 of the principal Act, for sub-section (7), the following shall be substituted, namely:—

“(7) In case of emergency warranting immediate action to be taken, in respect of powers not vested in him, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary after recording reason in writing and shall place the matter before the authority, competent to exercise such powers, for confirmation in its next following meeting but not later than sixty days, failing which the action taken by him shall cease to have any effect and if the action taken by the Vice-Chancellor is not confirmed by such authority, the same shall also cease to have any effect :

Provided that such emergency powers shall not be exercised by the Vice-Chancellor for making any appointment to any position or assignment or removal of any incumbent from such position or assignment :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget."

10. For section 30 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution
of section
30.

"30. Registrar.—(1) There shall be a Registrar in the University who shall be *ex-officio* Member-Secretary of the Senate, Board and Academic Council of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of this Act, the Registrar shall be appointed, by the State Government from amongst the officers who have put in at least five years service in the Indian Administrative Services or at least nine years service in Himachal Pradesh Administrative Services under the State Government, failing which by the Board on the recommendations of the selection committee, as may be constituted for the purpose under the Statutes.

(3) The Registrar shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes."

11. In section 31 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

Amendmen
of section
31.

"(1) There shall be a Comptroller who shall be appointed by deputation from amongst the Officer(s) of the Himachal Pradesh Subordinate Accounts Service (Ordinary Branch) not below the rank of Deputy Controller, and shall be responsible to the Vice-Chancellor of the University for all matters pertaining to the accounts of the University including the preparation and presentation of the budget and statement of accounts."

12. After section 39 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion
of section
39-A.

"39-A. *Creation of posts etc.*—No post, position and assignment created by the University shall have any effect unless approved by the State Government."

3. Benefits in case of :

(i) Death	Rs. 2.00 lakh
(ii) Permanent total disablement	Rs. 2.00 lakh
(iii) Loss of one Limb+one eye or both eyes or both limbs.	Rs. 2.00 lakh
(iv) Loss of one limb/eye	Rs. 1.00 lakh

This scheme will not cover the workers and work charged staff of Government departments, Boards, Corporations, Universities and autonomous bodies or who are presently covered under similar scheme being implemented by New India Assurance Co. Ltd. Shimla.

A. Mode of Premium Payment :

- (1) The State Government will make advance payment of Rs. 1,36,50,000/- on account of premium for approx 1,50,000 employees of Government departments to United India Insurance Co. Ltd., Timber House, Cart Road, Shimla. Employees joining service after the inception date of the policy will be covered under the scheme from next renewal of the policy.
- (2) All Boards, Corporation, Universities, Autonomous Bodies would make advance payment of premium to United India Insurance Co. Ltd., Timber House, Cart Road, Shimla-171001 by a single Cheque/draft in favour of United India Insurance Company Ltd., Shimla.

B. Mode of Premium recovery :

- (1) All the Head of Departments would ensure supplying a copy of this notification to all the DDOs under their administrative control with suitable instructions to recover an amount of Rs. 91/- from each employee from their next payable salary and this recovery would be credited to Receipt Head 0235-60-105-02. Since the policy is on compulsory basis, recovery has to be ensured from all the Regular, Adhoc, Contractual, part time and daily waged employees not later than the salary/wages for the month of January payable in February, 2005.
- (2) The Boards/Corporations/Universities/Autonomous Bodies may adopt any suitable measure to recover the premium from their employees as they may deem fit.

C. Claims :

All claims will be dealt directly by Divisional Office, United India Insurance Co. Ltd., Timber House, Cart Road, Shimla-171001, only without any involvement of any higher or lower level office and settled within a week's time after completion of requisite claim formalities which are as per Annexure A. The head of Departments will lodge the claims with the insurance Company within 30 days of occurrence of any accident in the specified forms enclosed at Annexure-A.

The scope of cover and specimen copies of claims intimation letter and claims form would be as per Annexure "I+II".

Action may be ensured at the earliest possible on A & B above.

By order,

YOGESH KHANNA,
Principal Secretary (Finance).

ANNEXURE-A

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD
TIMBER HOUSE, CART ROAD
SHIMLA-171001

SCOPE OF COVER OF GROUP PERSONAL ACCIDENT POLICY FOR
EMPLOYEES OF STATE OF HIMACHAL PRADESH.

- (a) IF ACCIDENTAL INJURY SHALL WITHIN 12 (TWELVE) CALENDAR MONTHS OF ITS OCCURRENCE BE THE SOLE AND DIRECT CAUSE OF DEATH OF THE INSURED PERSON, THE CAPITAL SUM INSURED OF Rs. 2,00,000/- STATED IN THE SCHEDULE HERETO SHALL BE APPLICABLE TO SUCH INSURED PERSON.
- (b) IF SUCH INJURY SHALL WITHIN 12 (TWELVE) CALENDAR MONTHS OF ITS OCCURRENCE BE THE SOLE AND/OR DIRECT CAUSE OF THE TOTAL AND IRRECOVERABLE LOSS OF:—
 - (i) THE SIGHT OF BOTH EYES OR THE ACTUAL LOSS BY PHYSICAL SEPARATION OF THE TWO ENTIRE HANDS OR TWO ENTIRE FEET OR ONE ENTIRE HAND AND ONE ENTIRE FOOT OR SIGHT OF ONE EYE AND SUCH LOSS OF ONE ENTIRE HAND OR ONE ENTIRE FOOT OF THE INSURED PERSON THE CAPITAL SUM INSURED STATED IN THE SCHEDULE HERETO SHALL BE APPLICABLE TO SUCH INSURED PERSON.
 - (ii) USE OF TWO HANDS OR TWO FEET OR OF ONE HAND AND ONE FOOT OR SUCH LOSS OF SIGHT OF ONE EYE AND SUCH LOSS OF USE OF ONE HAND OR ONE FOOT OF THE INSURED PERSON THE CAPITAL SUCH INSURED STATED IN THE SCHEDULE HERETO APPLICABLE TO SUCH INSURED PERSON.
- (c) IF SUCH INJURY SHALL WITHIN 12 (TWELVE) CALENDAR MONTHS OF ITS OCCURRENCE BE THE SOLE AND DIRECT CAUSE OF THE TOTAL AND IRRECOVERABLE LOSS OF :—
 - (i) THE SIGHT OF ONE EYE OR THE ACTUAL LOSS BY PHYSICAL SEPARATION OF ONE ENTIRE HAND OR ONE ENTIRE FOOT OF THE INSURED PERSON 50% (FIFTY PERCENT) OF THE CAPITAL SUM INSURED STATED IN THE SCHEDULE HERETO APPLICABLE TO SUCH INSURED PERSON.

- (ii) USE OF ONE HAND OR ONE FOOT OF THE INSURED PERSON WITHOUT PHYSICAL SEPARATION; 50% OF THE CAPITAL SUM INSURED STATED IN SCHEDULE HERETO APPLICABLE TO SUCH INSURED PERSON.

NOTE.—FOR PURPOSE OF CLAUSES (B) ABOVE PHYSICAL SEPARATION, OF A HAND OR FOOT MEANS SEPARATION OF HAND AT OR ABOVE THE WRIST AND/OR OF THE FOOT AT OR ABOVE THE ANKLE.

- (d) IF SUCH INJURY SHALL AS A DIRECT CONSEQUENCE THEREOF, IMMEDIATELY PERMANENTLY TOTALLY AND ABSOLUTELY DISABLE THE INSURED PERSON FROM ENGAGING IN OR BEING OCCUPIED WITH OR GIVING ATTENTION TO ANY EMPLOYMENT OR OCCUPATION OF ANY DISCRPTION WHATSOEVER THEN A LUMP SUM EQUAL TO 100% OF THE CAPITAL SUM INSURED STATED IN THE SCHEDULE HERETO APPLICABLE TO SUCH INSURED PERSON.
- (e) REIMBURSEMENT OF EXPENSES OF CARRIAGE OF DEAD BODY POLICY WILL REIMBURSE THE ACTUAL EXPENSES INCURRED FOR THE CARRIAGE OF THE DEAD BODY OF THE INSURED PERSON (DEATH DUE TO ACCIDENT) TO THE PLACE OF RESIDENCE SUBJECT TO MAXIMUM OF RS. 1000/-.
- (f) CLAIM INTIMATION TO BE SUBMITTED IMMEDIATELY BUT NOT LATER THAN THIRTY DAYS OF ACCIDENT.

ENCLS : A. CLAIM INTIMATION LETTER.

B. CLAIM FORM.

ANNEXURE-I

CLAIM INTIMATION LETTER
(Specimen Copy)

Dated.....

The Divisional Manager,
United India Insurance,
Timber House, Cart Road,
Shimla-171 001
Tel.: 2625397
2625392
Mob.: 94180-17052

SUB.: INTIMATION OF LOSS UNDER GROUP PERSONAL ACCIDENT POLICY.

Sir,

It is to intimate you that Sh.....s/o Sh.....
R/o.....working as.....in
department of.....posted at.....has
died/lost following body parts.....
Suffered permanent total disability due to accident of.....on

dated.....You are requested to register the said claim at the earliest in favour of insured against Group Personal Accident Insurance Scheme.

Thanking you,

(.....)

SIGNATURE

(Not in case of death)

DATED.....

PLACE.....

(.....)

Countersigned by Head of the Office/Department

Document to be submitted in event of a claim :

(1) Claim intimation immediately after knowledge of occurrence.

(2) Claim form alongwith

(i) FIR

(ii) Postmortem report in event of death/death certificate from state authority.

(iii) Treatment and disability certificate in event of permanent total disability/permanent partial disability.

NOTE.—ALL DOCUMENTS SHOULD BE DULY ATTESTED BY HEAD OF DEPARTMENT.

FILE: JPCCLINT

ANNEXURE-II

(CLAIM FORM GROUP PERSONAL ACCIDENT POLICY)

(Not be taken as admission of any liability)

1. NAME OF INSURED :.....
NAME OF LIFE INSURED :.....
DESIGNATION :.....
PARENTAGE :.....
RESIDENTIAL ADDRESS :.....

POSTED AT :.....
DEPARTMENT :.....
PREMIUM PAID ON :.....POLICY NO.....
2. AGE :.....SEX :.....
DATE OF ACCIDENT :.....TIME OF ACCIDENT:.....
HOW DID ACCIDENT OCCUR:.....
WITNESS OF ACCIDENT:.....HIS NAME:.....
ADDRESS:.....
.....
3. NATURE OF INJURY RECEIVED :.....
NATURE OF DISABLEMENT :.....
NAME & ADDRESS OF HOSPITAL :.....
PRESENT STATE OF INJURY/HEALTH :.....

WHEN AND WHERE CAN INSURED-
PERSON BE VISITED BY OFFICIAL INSURERS:.....

4. DETAIL OF POLICE REPORT LODGED
WITH F. I. R. NO. AND DATE:.....
ULTIMATE LOSS :..... (Loss of body parts, PTD)
DETAILS OF BODY PARTS LOST:.....
DETAILS OF PERMANENT TOTAL DISABILITY:.....
POSTMORTEM/TREATMENT TAKEN FROM:.....

5. I hereby declare that the foregoing statements are true to the best of my knowledge and belief and I have not attempted to conceal any relevant pertinent information. In case of any false/fraudulent/untrue averment whatsoever the said policy shall be void *ab-initio* and my right/my claim for compensation will be forfeited.

(.....)
SIGNATURE
(Note in case of death)

DATED.....
PLACE.....

(.....)
Countersigned by Head of the
Office/Department

FOLLOWING DOCUMENTS ENCLOSED IN SUPPORT OF THIS CLAIM:

1. FIR
2. Post Mortem Report
3. Brief Accident Report by the Department
4. Any other Document.